श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि हड़ताल से पहले बैठक करना सम्भव होता तो हम अवश्य बैठक करते।

DR. BAPU KALDATE (Aurangabad) : Issue of revising the pay structure is pending for the last ten years and it is natural if employees feel somewhat agitated. The Government should persuade the employees not to resort to indefinite strike. The Government should act firmly and look to the interests of the workers. The Janta Government will not favour the exploitors and profiteers. I want to know the course of action to be adapted in case this meeting fails.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस बात से सहमत हूं कि इनके वेतन ढांचे का पुनरीक्षण पिछले दस सालों से न हो सका। सत्ता ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर ही हमने अधिसूचना जारी कर दी थी। इससे सिद्ध होता है कि हम इस समस्या से चिंतित थे। मैंने कर्मचारियों से अपील कर दी है और मुझे आशा है कि अब लगातार अनीश्चित हड़ताल नहीं होगी। मैं इसे टालने के लिये यथासम्भव प्रयास करूंगा हमें वार्ता कुछ आशाओं के साथ करनी चाहिये। मुझे आशा है कि वार्ता सफल होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल का नोटिस आने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की? इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। पिछली तारीख से लाभ देने के बारे में मंत्री महोदय ने आश्चर्यजनक बातें कहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिफारिश को 1 जून 1975 से लागू किया जाना था लेकिन अब अप्रैल, 1977 से किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? कर्मचारियों को अंतरिम मजूरी की राशि एक या दो सप्ताह तक क्यों नहीं दी गयी (**व्यवधान**)।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार ने हड़ताल के बारे में कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया है। नोटिस मालिकों को दिया गया होगा (**व्यवधान**)। हम अधिसूचना को कार्यान्वित करना चाहते थे। सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है जिसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। अधिसूचना पर वार्ता करने से अनेक समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

परिशोधित अधिसूचना का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बारे में भ्रांति है। 20 महीने तक अंतरिम मजूरी को न दिये जाने के लिये यह सरकार उत्तरदायि नहीं है। जब हम सत्ता में आये हैं तो हमने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे हम लागू करेंगे।

प्रधान मंत्री द्वारा लंदन में राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT BY PRIME MINISTER ON HIS PARTICIPATION IN COMMONWEALTH PRIME MINISTERS' CONFERENCE IN LONDON

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सदन को मालूम है, राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के बाद, आज सुबह में यहां वापस आया हूं। इस यात्रा के दौरान, ईरान के शाहंशाह के निमंत्रण पर कुछ घंटे मैं तेहरान रुका, और फ्रांस के राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में एक दिन के लिए पेरिस भी रुका। दोनों हमारे पुराने और सम्मानित मित्र हैं जिनके साथ मैत्री और मज़बूत करके मुझे खुशी हुई। इनके साथ अपनी बातचीत में हम ने केवल अपने सामान्य हितों के मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाने में समर्थ हुए और विश्व की समस्याओं खास तौर से ऊर्जा के संबंध में हमने अपने दृष्टिकोण में काफी समानता पाई।

हमारी सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। यह संतोष की बात है कि लोकतांत्रिक चुनाव तथा व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन से भारत की इज्जत न केवल फिर से लौटी है, बल्कि इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह इज्जत बढ़ी है। शाहंशाह, ब्रिटिश सरकार तथा फ्रांस के नेताओं के साथ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य राज्याध्यक्षों, समाचार माध्यम तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी बातचीत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली के प्रति वचनबद्धता तथा निष्ठा में भारतीय जनता की परिपक्वता की सराहना हुई है। विभिन्न मौकों पर जब मुझ से प्रश्न पूछे गये तो मैंने बताया कि प्रजातंत्र की जड़ भारत की प्राचीन सभ्यता में जैमी है। विदेशी शासन तथा इमरजेंसी जैसी पथभ्रष्टता हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय स्वभाव के विपरीत है। हाल के चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता में निर्भय होकर निर्णय करने तथा

अपने शासकों को चुनने का जन्मजात नैतिक साहस है। निजी और सार्वजनिक तौर पर सभी संबंधित व्यक्तियों को विश्वास दिला चुका हूं कि भारत की नई सरकार, जिसमें भारतीय जनता ने आस्था व्यक्त की है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है; और यह इस बात का सुनिश्चित करेगी कि हमारे संविधानिक सिद्धांतों को फिर कभी विकृत न किया जा सके। मुझ से कहा गया कि भारतीय जनता का असाधारण साहस और दूरदर्शिता एक गुण था और सम्पूर्ण विश्व के समान विचार रखने वाले लोगों के लिए एक प्रोत्साहन था। इसलिए जो भी सफलता, आदर-सत्कार तथा सम्मान मुझे मिला वह हमारी जनता की प्रशस्ति है जिन्होंने दुनिया के सामने अपने फसले से लोकतंत्रात्मक मूल्यों में अपनी आस्था, निरंकुशता के प्रति अपनी असहमति तथा एक ऐसी सरकार चुनने के विवेक का प्रदर्शन किया जिसमें उनका विश्वास हो कि वह सेवा कर सकती है।

राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्ष सम्मेलन आठ साल बाद लंदन में हुआ। मैं यही कहना चाहुंगा कि यह राष्ट्रमण्डल स्वतंत्र राज्यों की एक संस्था है जो अपनी आन्तरिक और विदेशी नीतियों में पूरा स्वतंत्र हैं। इनमें कूछ ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखते हैं कुछ दूसरे हैं जिन के यहां उनकी अपनी राजतंत्रिय प्रणाली है और कुछ हमारे जैसे भी हैं जहां पूर्णरुप से गणतंत्रात्मक संविधान है, लेकिन अपने देश के हितों के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने के लिए वे स्वतंत्र हैं और सामान्य हितों की समस्याओं के प्रति सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं।

यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि सदन को मालूम है, वहुजातीय तथा बहुमहाद्वीपीय राष्ट्र समुदाय है जिसमें मानव-जाति का एक चौथाई भाग है। इसमें कुछ अमीर तथा मजबूत हैं और कुछ छोटे तथा कमजोर हैं। लेकिन सभी हितों की समानता तथा अन्योन्याश्रय के तर्क को मानते हैं। जहां तक जनसंख्या का सवाल है, भारत इसके कुल निवासियों के आधे से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह राष्ट्र मण्डल को न तो बनावट है न यह विस्तृत कार्याविधियों से नियमित है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र समुदाय की विभिन्नता का दर्पण है। इसकी विशेषता है अनौपचारिकता तथा सहयोग की परम्परा, जो कि शायद अद्वितीय है। यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि अब इसका गठन हुआ है, एक ऐसे प्रकार का संतुलन प्रदान करता है जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो आगे सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रमण्डल के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है।

यह सम्मेलन मेरे पुराने दोस्त तथा यू० के० के प्रधान मंत्री श्री जेम्ज़ कैल्हन की अध्यक्षता में हुआ। वे एक प्रशंसनीय अध्यक्ष साबित हुए, जिनके मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव और विभिन्न प्रश्नों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने में योगदान मिला, जो सम्मेलन के निर्णयों में अन्तर्निहित है। उनमें और विभिन्न देशों के राज्याध्यक्षों और नेताओं में मैंने यह एक प्रबल इच्छा देखी कि एक रचनात्मक रवैया अपनाया जाए और एक दूसरे से दूर जाने की बजाय नज़दीक आया जाए। इस सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुए वे मानवीय अधिकार, दक्षिण अफ्रीका, हिन्द महासागर, उत्तर दक्षिण आर्थिक संबंध, विकासशील देशों की समस्याओं जैसे नाजूक विषय थे, जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक था। लेकिन सम्मेलन के अन्त में जो विज्ञप्ति जारी की गई उससे पता चलेगा कि सभी, अपने राष्ट्रीय विचारों का परित्याग किये बिना एक सर्व-सम्मति पर पहुंचने के इच्छुक हैं।

हमने सभी विषयों पर, खास तौर से विश्व की आर्थिक समस्याओं, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में, हमने विकासशील देशों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के अनुकूल तकनीक अपनाने के औचित्य और महत्व पर प्रकाश डाला। हमने इस बात पर जोर दिया कि मशीन मनुष्य की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, न कि मनुष्य उसका गुलाम बन जाए। हमने बतलाया कि विकास प्रयास और आर्थिक प्रगति छोटे और निर्धन पर ध्यान दे और बड़े और भव्य के प्रलोभन में न आये। खाद्य उत्पादन, भण्डारन, वितरण तथा ग्रामीण विकास के संघटित कार्यक्रम तथा औद्योगीकरण हमारे बयानों में जोरदार ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं।

परसों लंदन में जो विज्ञप्ति जारी की गई, जिस पर माननीय सदस्यों का पहले ही ध्यान गया होगा, वह विषयों के क्षेत्र तथा विचार विमर्श की गहराई, तथा सम्मेलन की व्यापक सर्वसम्मति प्रतिविम्बित करती है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हिन्द महासागर, साइप्रस, और अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच बढ़ती खाई जैसी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं और राष्ट्रमण्डल के भीतर आर्थिक, व्यापारिक तथा कार्यात्मक सहयोग के लिए व्यावहारिक सिफारिशें हैं।

कई राष्ट्रमण्डल देश यूगाण्डा के संबंध में मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर बहुत चिन्तित थे। 1971 में राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों द्वारा अपनाए गये "द सिंगापुर डिक्लेरेशन आफ प्रिंसिपुल्स ने सभी राष्ट्रमण्डलीय सरकारों की मौलिक अधिकारों में आस्था और मानवीय मर्यादा तथा समानता के प्रति आदर की पुष्टि की। जैसा कि सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि हम इन सिन्द्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं। हालांकि सम्मेलन में इस विषय पर हुई चर्चा मतभेदों से मुक्त नहीं थी, लेकिन अन्ततोगत्वा राष्ट्रमण्डल परम्पराओं के अनुरूप मोटे तौर पर एक हल निकाला गया जो सबको स्वीकार्य था।

यहां पर राष्ट्रमण्डल सचिवालय के कार्य की सराहना करना उपयुक्त होगा ऐसा मेरा ख्याल है। अभी यह श्री रामफल के योग्य नेतृत्व में है, जो पहले गुयाना के विदेश मंत्री थे। राष्ट्रमण्डलीय देशों में विभिन्न व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्पर्क बनाये रखने तथा अन्तः राष्ट्रमण्डल सहयोग के प्रसार में नवीन भूमिका निभाने जैसे कई कार्यों के अतिरिक्त यह सचिवालय राष्ट्रमण्डलीय देशों में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल की है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इस प्रकार का सहयोग बढ़ाने के राष्ट्रमण्डल सचिवालय के प्रयासों के, अपेक्षाकृत कम खर्च में, लाभदायक परिणाम निकले हैं। हम भारत के लोग इस सहकारी कार्यक्रम में योगदान देकर ही खुश नहीं हैं, बल्कि इससे हमें भी लाभ मिला है, खास तौर से अपने व्यापार बढ़ाने में मिला है।

इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अतिरिक्त इसका महत्व यह था कि इसने राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के कई लब्धप्रतिष्ठ नेताओं के साथ अनौपचारिक तथा द्विपक्षीय सम्पर्क के लिए अवसर प्रदान किये। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री कैल्हन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय समस्याओं के संबंध में बंगलादेश के राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुए। राष्ट्रपति ज़िया और में इस बात से सहमत हुए कि वह हमारे राष्ट्रीय तथा सामान्य हित में है कि हमारे संबंध अच्छे पड़ोसी जैसे हों। कनाडा के प्रधान मंत्री के साथ हमने उन समस्याओं की समीक्षा की जो हमारे सद्भावपूर्ण संबंधों के रास्ते में उत्पन्न हुई और इस बात से सहमत हुए कि अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतियों के चौखटे में ऐसे प्रयास किए जाएं जिनसे नाभिकीय विज्ञान तथा तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में लाभदायक सहयोग और भारत-कनाडा मैत्री फिर से कायम हो। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री और मैंने यह महसूस किया कि एशिया और प्रशांत महासागर की राष्ट्रमण्डलीय सरकारें अपनी-अपनी भौगोलिक दृष्टि से सामान्य हित के क्षेत्र में लाभदायक संबध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ओर जाम्बिया के राष्ट्रपति कौंडा, मरिशस के सर सीबूसागर रामगुलाम और अफ्रीकी राष्ट्रों के अन्य नेतागण और दूसरी ओर जमाइका के प्रधान मंत्री और कैरिबीयन नेतागण के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने यह महसूस किया कि राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को संजोये रखा है और अपने सहयोग बढ़ाने की इच्छा प्रगट की है। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कई सहयोगियों से मिले और मेरी तरह उनकी भी राय थी कि राष्ट्रमण्डल के हरेक हिस्सेदार भारत की नई सरकार के साथ न केवल संबंध बनाये रखना चाहते हैं बल्कि उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। उन्होने कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की जिनका संबंध विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से है।

इस यात्रा से यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले कई भारतीय प्रतिनिधियों तथा विश्व समाचार माध्यमों के लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। सभी जगह भारत के प्रति एक नई दिलचस्पी देखने को मिली। चाहे वह भारतीय समुदाय हो अथवा समाचार माध्यम हो, लोकतंत्रात्मक भारत में एक नई आस्था आई है और उससे एक नई आशा जगी है। 12 जून को लंदन में भारतीय समुदाय की एक विशाल बैठक हुई, जिसमें अपनी जनता की ओर से मैंने उनकी अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा का स्नेहयुक्त उत्तर दिया। साथ ही, मैंने उनसे कहा कि कि वे इस प्राचीन भूमि की परम्पराओं के योग्य बने और अपने वर्तमान अधिवासी देश के लोगों के साथ सामाजिक व्यवस्था की दिशा में प्रयास करते हुए उनका हृदय जीतें।

महोदय, इस यात्रा से मुझे स्पष्ट हो गया है कि लगभग प्रत्येक देश ने हमारे देश के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं चाही, बल्कि हमारी राजनीतिक विजय और आर्थिक उपलब्धियों से खुश हुये ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा कोई राष्ट्रमण्डलीय देश नहीं था जो हमारी नितियों को समझने के बाद, जिनके प्रति हमारी वर्तमान सरकार वचनबद्ध है, दुर्भावना रखे या हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को अनुचित आलोचना करे। यह मान लिया गया है कि हमने जिस सच्ची गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन और अनुसरण किया है वह हमारे हितों की ही रक्षा नहीं करती,

बल्कि भारत को अपने संबंधों तथा स्थायी विश्व व्यावस्था के विचार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाती है। लेकिन हम अच्छी तरह यह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर हम जो भूमिक अदा कर सकते हैं वह हमारी घरेलू ताकत तथा आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वावलाम्बन पर निर्भर करती है।

जैसा कि पहले कहा है, मैं तेहरान में ईरान के शाहंशाह से मिला। उनके साथ बातचीत के दौरान मुझे और हमारे विदेशी मंत्री को प्रधान मंत्री हुवेदा और विदेश मंत्री खालतबारी से मिलकर खुशी हुई। हमारे विचार-विमर्श का क्षेत्र व्यापक था और इससे ईरान की सद्भावना और हमारे सहयोग की स्थायी शक्ति का परिचय मिला। हम इस बात पर भी सहमत हुये कि हम दोनों इस क्षेत्र के स्थायित्व और प्रगति में समान दिलचस्पी रखते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति के अनुरोध पर पैरिस रुकने से सामान्य हित के कई मामलों पर विचार-विमर्श करने का मौका मिला। राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी एस्टेंग तथा प्रधान मंत्री बार्रे के साथ मेरी बातचीत अत्यंत मैत्रीपूर्ण रही और फ्रांस के साथ हमारे निकट और लाभदायक संबंधों की आशा और बढ़ी।

अणु अस्त्रों के प्रचुर मात्रा में न बनाये जाने के संदर्भ में नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में सम्बद्ध प्रश्न मेरे साथ कई बार बातचीत में उठाये गये। मुझे अपनी स्थिति दोबारा समझाने का मौका मिला, जो कई बार इस देश में और बाहर भी स्पष्ट की जा चुकी है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही नाभिकीय उर्जा के विकास में दिलचस्पी रखते हैं।

महोदय, इस राष्ट्र समुदाय के साथ लाभदायक संबंध बढाने का पहले से ज्यादा अब अवसर है। पिछले तीन महीनों में जब से हमने कार्यभार संभाला, गुट निरपेक्ष के रचनात्मक दबाव के चौखटे में हमने अपने पुराने दोस्तों को विश्वास दिलाया है कि निकट और सुदूर भविष्य में उनके साथ हमारा संबंध बेहतर होता जायेगा। हम दावा कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों की हमारी दोस्ती में ज्यादा आस्था है और इस सम्पूर्ण उप महाद्वीप में तनाव कम है और अब ये ज्यादा सहयोग देने के इच्छुक हैं। राष्ट्रमण्डल सम्मेलन तथा इस विदेश यात्रा से विश्व के सभी हिस्सों के नेताओं का यह स्पष्ट करने का मौका मुझे मिला कि यह भारत सरकार जिसे भारतीय जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और एक बार फिर गांधी जी की दृष्टि और आदर्श से प्रेरणा मिली है, एक ऐसा शांतिपूर्ण विश्व बनाने में पीछे नहीं रहेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयत्नशील रहे।

कुल मिलाकर, तीस राष्ट्रमण्डलीय देशों से ज्यादा राज्याध्यक्षों, ईरान के शाहंशाह तथा फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मिलने से इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की इज्जत बढ़ी है और इस देश के प्रति अब ज्यादा सद्भावना है।

लोक सभा के महासचिव श्री श्यामलाल शकधर के पद से मुक्त होने और श्री अवतार सिंह रिखी की लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्ति के बारे में घोषणा

Announcement RE : Relinquishing of office by Shri S. L. Shakdhar, Secretary General of Lok Sabha and Appointment of Shri Autar Singh Rikhy as Secretary, Lok Sabha.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि लोक सभा के महासचिव श्री श्यामलाल शकधर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होने पर कल अपना पद त्याग रहे हैं। ये 13 वर्षों से लोक सभा के महासचिव रहे हैं। इस सभा की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये संसदीय प्रक्रिया बनाने हेतु इनका योगदान सराहनीय रहा है। प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी दल के हों, इनका परामर्श लेते रहे हैं।

श्री शकधर को विश्व के संसदीय क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। वे अनेक संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य रहे हैं। य अर्न्तसंसदीय संघ, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ जैसी संसदीय संस्थाओं से सम्बद्ध हैं; 1973 में ये संसद महासचिव संघ के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गये जोकि विश्व की संसदों के महासचिवों के बीच इनको लोकप्रियता का प्रतीक है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री शकधर की नियुक्ति उनकी सेवा का प्रमाण है। हमें इनका अभाव खटकेगा। इस सभा के लिये इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें सभा का अवैतनिक अधिकारी नियुक्त करता हूं।